पांच प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने, अखबारी कागज और स्टेपलर पर सख्ती का दावा, लेकिन रिपोर्ट और कार्रवाई का इंतजार बरकरार

सैंपलिंग या सिर्फ संदेश? खाद्य विभाग की कार्रवाई पर उठते सवाल

हरिभूमि न्यूज ⏭ जुन्नारदेव

बरसात के मौसम में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य विभाग एक बार फिर सक्रिय नजर आया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य निरीक्षक श्रीमती संध्या मार्को ने नगर के पांच प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। साथ ही होटल और मिठाई दुकानों के संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य सामग्री को ढंककर रखने तथा अखबारी कागज और स्टेपलर पिन का उपयोग नहीं करने के निर्देश भी दिए गए।

कार्रवाई के दौरान प्रेमता होटल, गुप्ता स्वीट्स, होटल पप्पू और हिमांशी ट्रेडर्स सहित पांच प्रतिष्ठानों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए गए। विभाग का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यदि कोई नमूना मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध जुर्माना एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।खाद्य निरीक्षक संध्या मार्को ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अब खाद्य सामग्री को अखबारी कागज में लपेटकर देना पूर्णतः प्रतिबंधित है। शोधों में अखबार की स्याही में मौजूद रसायनों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। इसी तरह स्टेपलर पिन का उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

हालांकि विभाग की इस कार्रवाई के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी सैंपलिंग कार्रवाई समय-समय पर दिखाई तो देती है, लेकिन उसके परिणाम शायद ही कभी सार्वजनिक किए जाते हैं। जिन प्रतिष्ठानों से नमूने लिए जाते हैं, उनकी जांच रिपोर्ट कब आती है, कितने नमूने फेल होते हैं और किन-किन दुकानदारों पर वास्तव में कार्रवाई होती है, इसकी जानकारी आम जनता तक शायद ही पहुंचती है।

यही कारण है कि खाद्य विभाग की कार्रवाई को लेकर लोगों में संदेह बना रहता है। यदि किसी

होटल या मिठाई दुकान का नमूना अमानक पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? यदि कार्रवाई होती है तो उसका प्रभाव बाजार में दिखाई क्यों नहीं देता? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर विभाग को देना चाहिए।

बरसात के मौसम में नगर के कई होटल, ढाबे और खाद्य प्रतिष्ठानों में आज भी गंदगी, खुले में रखी खाद्य सामग्री, मक्खियों की भरमार, अखबारी कागज का उपयोग और कई स्थानों पर स्टेपलर पिन का प्रयोग खुलेआम देखा जा सकता है। यदि नियम पहले से लागू हैं तो फिर इनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए नियमित निरीक्षण क्यों नहीं किए जाते?

यह भी सवाल उठता है कि खाद्य विभाग पूरे वर्ष सक्रिय निगरानी क्यों नहीं करता। यदि विभाग हर महीने वेतनभोगी अमले के साथ कार्यरत है तो प्रत्येक होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाता है? क्या इसके लिए कोई निर्धारित कैलेंडर या मानक प्रक्रिया है? यदि है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ सके।

स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्यवाही

निस्संदेह खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई स्वागत योग्य है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन कराना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन केवल सैंपल लेकर फोटो जारी कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। वास्तविक सफलता तब होगी जब जांच रिपोर्ट समय पर सार्वजनिक हो, दोषी प्रतिष्ठानों के नाम सामने आएं, उन पर कठोर कार्रवाई हो और नियमित निरीक्षण के माध्यम से बाजार में यह संदेश जाए कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जब तक कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी और उसके परिणाम जनता के सामने नहीं आएंगे, तब तक ऐसे अभियान दिखावटी होने का आरोप झेलते रहेंगे। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य केवल सैंपल लेना नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की प्रभावी रक्षा करना है। इसके लिए विभाग को निरंतर, पारदर्शी और परिणाम आधारित कार्रवाई करनी होगी, तभी ऐसी मुहिम का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

छापेमारी नहीं, नियमित कार्रवाई ही बनेगी सड़क सुरक्षा की गारंटी

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में परिवहन विभाग ने लंबे अंतराल के बाद स्कूल वाहनों की जांच कर बिना परमिट और बिना फिटनेस संचालित बसों पर कार्रवाई की। एक बस जब्त की गई, कई वाहनों की जांच हुई और नौ चालकों से 62 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इससे कहीं बड़ा सवाल यह है कि यदि विभाग नियमित रूप से ऐसी कार्रवाई करे तो क्या जिले की सड़कों पर बिना परमिट और बिना फिटनेस वाले वाहन दिखाई देंगे? शायद नहीं।

संपादकीय : मनीष गड़करी

असल समस्या यह नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, बल्कि यह है कि कार्रवाई केवल अभियान तक सीमित रहती है। अभियान खत्म होते ही नियमों की अनदेखी फिर शुरू हो जाती है। यही कारण है कि कई बस संचालक बिना परमिट, बिना फिटनेस और अधूरे दस्तावेजों के साथ वाहन सड़कों पर उतारने का जोखिम उठाते हैं। उन्हें कहीं न कहीं यह भरोसा रहता है कि या तो जांच नहीं होगी, और यदि हुई भी तो मामला किसी तरह संभाल लिया जाएगा। यही मानसिकता नियमों की धज्जियां उड़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही है।

जिले में आज भी अनेक ऐसे वाहन संचालित हो रहे हैं जो बारात परमिट लेकर पूरे साल सवारी ढो रहे हैं। कई बसों की फिटनेस समाप्त हो चुकी है, लेकिन वे लगातार यात्रियों को ढो रही हैं। यह केवल मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। स्कूल बसों में बच्चों की जान और यात्री बसों में आम लोगों की सुरक्षा सीधे तौर पर परिवहन विभाग की सतर्कता पर निर्भर करती है।

परिवहन विभाग पर समय-समय पर आर्थिक लेनदेन और कार्रवाई में नरमी बरतने के आरोप भी लगते रहे हैं। चाहे ये आरोप पूरी तरह सही हों या नहीं, लेकिन यह धारणा अवश्य बन चुकी है कि विभाग की कमजोर निगरानी का लाभ कुछ वाहन संचालक उठाते हैं। यदि विभाग अपने ही कर्मचारियों की जवाबदेही तय करे और नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई करे, तो व्यवस्था में स्वतः सुधार आ सकता है।

अगले माह नागद्वारी मेला शुरू होने वाला है। हर वर्ष इस दौरान बड़ी संख्या में निजी बसें और अन्य वाहन श्रद्धालुओं के परिवहन में लगाए जाते हैं। इसी समय ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस वाहन चलाने और मनमाना किराया वसूलने की शिकायतें भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी केवल चेकिंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मेले से पहले विशेष अभियान चलाकर प्रत्येक वाहन की फिटनेस, परमिट और किराया व्यवस्था की सघन जांच करनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई ही यात्रियों को राहत दिला सकती है।

विभाग अक्सर स्टाफ की कमी का हवाला देता है, लेकिन यह तर्क अब जनता को स्वीकार्य नहीं है। यदि विशेष अभियान चलाकर एक दिन में दर्जनों वाहनों की जांच हो सकती है, तो नियमित निगरानी भी संभव है। जरूरत केवल इच्छाशक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही की है। सड़क सुरक्षा किसी एक दिन की कार्रवाई से नहीं, बल्कि निरंतर निगरानी और निष्पक्ष कार्रवाई से सुनिश्चित होती है।

परिवहन विभाग को यह समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी केवल चालान काटने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं को होने से पहले रोकना भी उसका दायित्व है। यदि बिना परमिट और बिना फिटनेस चलने वाले वाहनों के खिलाफ नियमित कार्रवाई की परंपरा विकसित की जाए, वाहन जब्ती और भारी जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहे तथा विभाग के भीतर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जाए, तो नियम तोड़ने वालों के हौसले अपने आप पस्त हो जाएंगे।

कंडम वाहन से हो रहा लकड़ी का अवैध परिवहन

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

अवैध रूप से पेड़ कटाई , फिर लकड़ी का अवैध परिवहन , वह भी बिल्कुल कंडम वाहन से ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है , ऐसा कोई जिगरा वाला ही कर सकता है और ऐसा जिगरा वाला बड़कुही का एक लकड़ी व्यापारी है । जिसका कंडम वाहन लकड़ी भरकर दिन दहाड़े लंबे समय से सड़कों पर दौड़ रहा है ।यूँ तो कोयलांचल में कई प्रजातियों के पेड़ हैं । इनमें नीलगिरी की भरमार है । जिनपर लकड़ी से जुड़े व्यवसाईयों की कुल्हाड़ी चलते हुए अक्सर देखी जा सकती है । छटाई के नाम पर पूरा का पूरा पेड़ काट कर उनका धड़ल्ले से परिवहन किया जाता है ।

जिन वाहनों से परिवहन किया जाता है , उनमें से अधिकांश वाहन परिवहन नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं । फिलहाल जिस वाहन की यहां बात की जा रही है , कंडम स्तिथि में है । इस कंडम वाहन में 2 से 3 टन माल भरकर भीड़ भरी सड़कों से गुजरना खतरे से खाली नहीं है । बावजूद इसके यह वाहन अक्सर चौकी , थानों यहां तक की वन विभाग के कार्यालय के सामने से गुजरता दिखाई देता है , पर मजाल है , कोई इसे रोक कर पूछताछ कर सके । बताया जाता है , कि यह वाहन बड़कुही के किसी लकड़ी व्यापारी का है । हाल - फिलहाल में इसके द्वारा चांदामेटा में न्यूटन की ओर जाने वाली सड़क वाले क्षेत्र में पेड़ कटाई कर ढुलाई की जा रही है ।

स्कूलों में अनफिट बसों में हो रहा बच्चों आवागमन

सौंसर। संतराचल के निजी स्कूलों,के साथ ही विशेषकर सांदीपनी स्कूल सौसर में संचालित हो रही बस आटो व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वर्तमान में सांदीपनि स्कूल सौसर में सरकार की ओर से बसों की व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरी में मनमर्जी से स्कूल में बसों गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। हाल ही में हुई पालक संघ की बैठक में अभिभावकों ने बसों की जर्जर स्थिति, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने,बढ़ता किराया,और परिवहन नियमों की अनदेखी को लेकर तीखी नाराजगी जताई थी। पालकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद, मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन ने सांदीपनी स्कूल मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने स्कूली बसों, ऑटो और मैजिक वाहनों की जांच की। चेकिंग में कई बसें और ऑटो 'अनफिट' पाए गए और उनमें क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। इस दौरान कई मासूम बच्चों को भारी बस्तों के बोझ के साथ नागपुर-छिंदवाड़ा मुख्य मार्ग पर पैदल स्कूल आते भी देखा गया।

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए 14 दिन बीते, 22 वर्षीय युवती का अब तक नहीं लगा सुराग

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा

परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार, युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, संदिग्धों पर कार्रवाई की मांग

जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बदनूर से 22 वर्षीय युवती रितु यादववंशी के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए लगभग 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक युवती का कोई सुराग नहीं लगा सकी है। इससे परिजनों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी और चिंता लगातार बढ़ रही है।

पीड़ित पिता कमलेश यादववंशी ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री को गांव के कुछ लोगों ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों पर संदेह है, वे पहले भी युवती को परेशान करते थे। परिवार का आरोप है कि यदि पुलिस शुरुआत से ही गंभीरता और तेजी से कार्रवाई करती, तो शायद अब तक युवती का पता लगाया जा सकता था।

परिजनों ने बताया कि 2 जुलाई को युवती घर से अचानक लापता हो गई थी। रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश के बाद नवेगांव थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। परिवार का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है और बेटी की सकुशल वापसी की उम्मीद कमजोर पड़ रही है।

इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर युवती की शीघ्र बरामदगी और शिकायत में नामजद संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक न्याय की गुहार लगाएंगे। पुलिस की साइबर टीम ऐसे मामलों में जल्द ही खुलासा कर देती है क्योंकि आरोपी निरंतर फोन का उपयोग तो कर ही रहा है ऐसे में साइबर सेल की सक्रियता आवश्यक परिणाम ला सकती है और गुमशुदगी का खुलासा कर सकती है।

800 किलो महुआ लाहन नष्ट, 3 प्रकरण दर्ज

पांढुर्णा। कलेक्टर पांढुर्णा नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशन तथा सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी.आर. वैद्य के मार्गदर्शन में जिले में अवैध शराब के विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण एवं विक्रय पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंगलवार को आबकारी वृत्त पांढुर्णा द्वारा ग्राम लांघा एवं गुजरखेड़ी में अवैध शराब के अड्डों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान दो चढ़ी हुई भट्टियां मिलीं। साथ ही नालों एवं जंगल में झाड़ियों के पास अवैध हाथ भट्टी महुआ शराब बनाने के लिए पन्नियों एवं ड्रमों में एकत्रित लगभग 800 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया। महुआ लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन निर्मूल्य होने के कारण विधिवत नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त कार्रवाई में वृत्त प्रभारी अनिकेत पटेल एवं आबकारी आरक्षक मुकेश रहांगडाले, अनुराग गोनेकर तथा श्रद्धा रहांगडाले उपस्थित रहे।

79 लीटर अवैध शराब और कार जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

चौरई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध कारोबारियों के विरूद्ध जारी रहेगा अभियान

हरिभूमि न्यूज ⏭ चौरई

जिले की चौरई पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 79.02 लीटर देशी एवं अंग्रेजी शराब तथा एक कार जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देश पर जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध

लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चौरई भारती जाट के नेतृत्व में थाना प्रभारी चौरई द्वारा गठित पुलिस टीम ने मंगलवार रात मुखबिर से सूचना मिलने पर कार्रवाई की। सूचना थी कि छिंदवाड़ा की ओर से चौरई की तरफ एक कार में भारी मात्रा में अवैध शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने छिंदवाड़ा रोड स्थित चोरगांव रेलवे ब्रिज के पास मुख्य मार्ग पर नाकाबंदी की। संदिग्ध कार क्रमांक MP-28-CA-9494 को रोककर तलाशी लेने पर उसमें 79.02 लीटर देशी मसाला एवं अंग्रेजी शराब बरामद हुई। आरोपियों से शराब के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने मौके से अभिषेक उर्फ आशीष धुर्वे (22) निवासी शिवपुरी, आदित्य पटेल (19) निवासी शिवपुरी तथा सुभाष मसराम (20) निवासी उमरिया ईसरा, थाना कुंडीपुरा को गिरफ्तार कर लिया।

माध्यमिक शाला प्रतापगढ़ बादला में महीनों से बंद पड़ा हैंडपंप

तामिया। परासिया पीएचई उपखंड के तामिया क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान निर्धारित मापदंडों के विपरीत खुदाई किए जाने के बावजूद संबंधित उपयंत्री ने ठेकेदार का पूरा मूल्यांकन कर भुगतान कर दिया। वहीं मिट्टी की खुदाई को मुरम दर्शाकर ठेकेदार को कथित रूप से अनुचित लाभ पहुंचाने का भी आरोप है। क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल टंकियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि उपयंत्री को वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण मिलने के कारण जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उपयंत्री की लापरवाही का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में मस्जिद के सामने खराब हैंडपंप को सुधारने के लिए लोगों को कई बार शिकायत करनी पड़ी, तब जाकर मरम्मत हो सकी।इसी तरह कई स्कूलों और आंगनबाड़ियों के हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। एकीकृत माध्यमिक शाला प्रतापगढ़ बादला में पहली से मिडिल तक 100 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन स्कूल परिसर का हैंडपंप खराब होने से बच्चों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। शिक्षकों का कहना है कि शिकायत किससे करें, क्योंकि पीएचई अधिकारियों के संपर्क नंबर तक कहीं प्रदर्शित नहीं हैं। इससे पेयजल व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने स्व. रामनाथ ओकटे को दी श्रद्धांजलि

छिंदवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे के भाई स्वर्गीय रामनाथ ओकटे की शोकसभा में उपस्थित होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर श्री यादव ने शोकाकुल परिवार से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा इस कठिन समय में उन्हें धैर्य एवं संबल बनाए रखने का आग्रह किया।

जिले में अभी तक 294.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

छिन्दवाड़ा। जिले की औसत वर्षा 1059 मि.मी. है तथा जिले में अभी तक 294.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 425.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले में 14 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान 0.0 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 14 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त 24 घंटों के दौरान जिले की तहसीलों में वर्षा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि जिले में एक जून से अभी तक तहसील छिन्दवाड़ा में 190.2, मोहखेड़ में 264.4, तामिया में 277, अमरवाड़ा में 310.2, चौरई में 359.4, हर्रई में 214.3, बिछुआ 242.5, परासिया में 207.3, जुन्नारदेव में 289, चांद में 417.9 और उमरेठ में 304.4 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय और आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के निर्देशों के बाद भी जिले में वर्षों से कार्यालयों, छात्रावासों और गैर-शैक्षणिक कार्यों में जमे शिक्षक

भोपाल के आदेश पर भी कायम 'अटैचमेंट राज', स्कूलों से ज्यादा दफ्तरों में दिख रहे शिक्षक

हरिभूमि न्यूज ⏭ छिंदवाड़ा, मनीष गड़करी

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल तथा आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि शिक्षकों और प्राचार्यों के सभी अनावश्यक अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें उनकी मूल पदस्थापना वाले विद्यालयों में भेजा जाए। आदेश का उद्देश्य साफ है शिक्षक कार्यालयों में बाबूगिरी करने के बजाय स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाएं। लेकिन छिंदवाड़ा जिले की स्थिति इन आदेशों से बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रही है।

जिले में शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में वर्षों से अटैचमेंट की ऐसी संस्कृति विकसित हो

चुकी है, जिसमें शिक्षक विद्यालयों की बजाय जिला कार्यालयों, विकासखंड कार्यालयों, छात्रावासों और अन्य प्रशासनिक इकाइयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही दो प्राचार्य और दो शिक्षक लंबे समय से गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी कई शिक्षकों से कार्यालयीन कार्य कराया जा रहा है। निर्वाचन शाखा, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य प्रशासनिक शाखाओं में भी वर्षों से शिक्षकों के अटैचमेंट बने हुए हैं।

सबसे चौंकाने वाला मामला ई-लाइब्रेरी का बताया जा रहा है, जहां एक शिक्षक ने अपनी लगभग 28 वर्ष की सेवा में पांच वर्ष भी नियमित शिक्षण कार्य नहीं किया। यदि यह तथ्य सही है तो यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षक पूरी सेवा कार्यालयों में कैसे गुजार रहे हैं?जनजातीय कार्य विभाग की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। यहां बड़ी संख्या में शिक्षक छात्रावासों में अधीक्षक बनकर वर्षों से कार्यरत हैं। अनेक मामलों में पूरा सेवाकाल छात्रावास संचालन में निकल जाता है और शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने नहीं पहुंचते। विभागीय जानकारों का कहना है कि छात्रावासों में वर्षों से जमे ऐसे कर्मचारियों के कारण पारदर्शिता और जवाबदेही भी प्रभावित होती है। समय-समय पर छात्रावासों में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल और आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल दोनों ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, तब भी जिले में वर्षों से जमे अटैचमेंटधारी शिक्षकों को क्यों नहीं हटाया गया? क्या नियम केवल दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ सामान्य शिक्षकों के लिए हैं, जबकि प्रभावशाली और पहुंच वाले शिक्षक कार्यालयों में ही बने रहेंगे? सूत्रों का कहना है कि आदेशों के बाद विभाग कुछ औपचारिक कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अपने ही कार्यालयों में वर्षों से जमे शिक्षकों को हटाने में अब भी हिचकिचाहट दिखाई दे रही है। यदि ऐसा होता है तो यह कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार वास्तव में शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहती है तो केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। जिले में पदस्थ प्रत्येक अटैचमेंटधारी शिक्षक और प्राचार्य की सूची सार्वजनिक की जाए। यह भी बताया जाए कि किस आदेश के तहत, किस अवधि के लिए और किस आवश्यकता के कारण उनका अटैचमेंट किया गया था। जिन मामलों में वैध कारण नहीं हैं, उन्हें तत्काल समाप्त किया जाए।

साथ ही उन अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो लोक शिक्षण संचालनालय और आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के आदेशों के बावजूद शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं। यदि आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो यह अभियान भी पूर्व की तरह कागजी साबित होगा।

शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि शिक्षक विद्यालय में रहें, छात्रावासों और कार्यालयों में नहीं। यदि शिक्षक फाइलों और कार्यालयीन काम में उलझे रहेंगे तो विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होना तय है। भोपाल से जारी निर्देशों का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि हर शिक्षक अपनी मूल जिम्मेदारी निभाए और विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि छिंदवाड़ा में लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल और आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के आदेशों का पालन निष्पक्ष रूप से होता है या फिर प्रभावशाली लोगों को बचाकर केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि इस बार भी वर्षों से जमे अटैचमेंटधारी शिक्षक और अधिकारी यथावत बने रहते हैं, तो यह संदेश जाएगा कि भोपाल के निर्देश भी जिला स्तर पर फाइलों से आगे नहीं बढ़ पाए।

कमीशनखोर है वेकोलि का सिविल विभाग: इंटक

मरम्मत कार्य में हो रहे भेदभाव के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

श्रमिक संगठन इंटक ने मंगलवार को पेंच कोयला क्षेत्र प्रबंधन पर जमकर निशाना साधा । वेकोलि के पेंच सिविल विभाग को कमीशन खोर बताया । साथ ही प्रबंधन पर कामगारों और इंटक के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया । पेंच - कन्हान कोयला महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा । वहीं क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक (ए पी एम) प्रबंधन की ओर से हो रही लापरवाहियों के लिए खेद जताया ।

परासिया विधायक और इंटक अध्यक्ष सोहन लाल वाल्मीकि के नेतृत्व में पेंच , कन्हान कोयला क्षेत्र में सक्रिय संगठन की विभिन्न इकाईयों के पदाधिकारियों ने कामगार कालोनियों में शुद्ध पानी , मानसून रिपेयरिंग कार्य , स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रमिक संगठन इंटक से जुड़े कामगारों की उपेक्षा , उनके साथ भेदभाव किए जाने आदि मुद्दों को लेकर महाप्रबंधक के नाम ए पी एम को ज्ञापन सौंपा । हाथों में झंडे लेकर श्रमिक नेता माह प्रबंधक कार्यालय पहुंचे । यहां प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे बाजी की ।

संगठन अध्यक्ष सोहन वाल्मीकि ने ए पी एम और सिविल इंजीनियर के समक्ष प्रबंधन को जमकर खरी - खोटी सुनाई । उन्होंने कहा , कि वेकोलि का सिविल विभाग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है । मानसून रिपेयरिंग कार्य अभीतक शुरू नहीं हुआ हुआ है । इंटक के द्वारा जिन कामगारों के मकानों की मरम्मत करने सूची दी गई है , उनके मकानों की मरम्मत नहीं की जा रही है । अन्य संगठनों के द्वारा दी गई सूची पर कार्य हो रहा है , ये भेदभाव क्यों ? इंटक से जुड़ा कामगार पहले वेकोलि का ही तो कामगार है । इंटक नेहरिया शाखा के मनोज तिवारी और असलम खान ने बताया , कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते आर ओ प्लांट खराब हो गया , जिससे कामगारों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है ।

इसी क्रम में यह भी बताया गया , कि हाल ही में झूर्रे में हुए खेल कार्यक्रमों में इंटक से जुड़े लोगों को तरजीह नहीं दी । इन सब बातों को लेकर विधायक ने प्रबंधन को अपनी कार्यशैली में उचित बदलाव करने को कहा , ऐसा नहीं होने पर प्रबंधन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी ।

कार्यक्रम में इंटक संयुक्त महामंत्री अलाउद्दीन खान , साबिर खान मनोज साहू सहित बड़ी संख्या में श्रमिक नेता मौजूद रहे । ज्ञापन कार्मिक प्रबंधक देवानंद बाहने ने लिया और प्रबंधन की ओर से हो रही लापरवाहियों पर खेद जताया और कमियों को दूर कर समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया ।

गंदगी के कारण गाय मर रही है-शिवसेना

छिन्दवाड़ा: पाठाढ़ाना स्थित आदर्श गौशाला में जो गौवश की मृत्यु हो रही है उसका मूल कारण गंदगी है अत्यधिक बरसात होने के कारण रूके हुये पानी एवं गौ शाला प्रागंण में गोबर समय पर नहीं उठने के कारण गंदगी फैल गयी जिसके कारण गाय मर रही है इस विषय पर शिवसेना द्वारा नगर निगम सहित संबंधित अधिकारियों को गौशाला में साफ सफाई व्यवस्था बनाने के लिये एक टीम कल भेजी जा रही है जिसमें गौसेवक एवं शिवसेना कार्यकर्ता की उपस्थिति में बेहतर साफ -सफाई व्यवस्था बनाकर गौरक्षा के कार्य को सफल बनाया जायेगा। गौसेवा कार्य में शिवसेना प्रमुख नितिन राय ने नगर के समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं सहित गौप्रेमी भाईयों से उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने की अपील की है।

नपा परासिया में तीन लोगों को मिली अनुकम्पा नियुक्ति

परासिया :- नगर पालिका परासिया में कार्यरत तीन कर्मचारियों की मृत्यु होने के उपरांत उनके उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई । मंगलवार को नपा अध्यक्ष विनोद मालवी ने सम्बंधित लोगों को नियुक्ति पत्र दिए ।ये नियुक्ति पत्र राजू पवार की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र हर्ष पवार (सहायक ग्रेड 3) , सतीश शर्मा की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र वैभव शर्मा और नन्द किशोर यदुवंशी की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र प्रशांत यदुवंशी को दिए गए । अध्यक्ष श्री मालवी ने दिवंगत कर्मचारियों के कार्यकाल को याद करते हुए उनके कार्यों की सराहना की व नव नियुक्त कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सलाह दी ।

भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन, संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प

सौंसर। भारतीय जनता पार्टी पांढुर्णा के जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड ने सोमवार को अपने सौसर स्थित निवास कार्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनसे संगठन को नई ऊर्जा देने का आह्वान किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड ने कहा कि किसान मोर्चा पार्टी का एक अत्यंत सशक्त और महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे।किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विलास खिरडकर ने भी नई टीम के प्रति विश्वास जताते हुए कहा कि यह कार्यकारिणी किसानों के हितों की रक्षा करने और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में प्रभावी कार्य करेगी।कार्यक्रम में किसान मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की गई, जिसमें मदन साहू, विजय आखरे, सुंदर पवार, सुभाष बालपांडे, हरिभाऊ बोबडे को उपाध्यक्ष; किशोर धुर्वे व रवि फरकसे को महामंत्री; महेश भादे, दिनेश भारत, राजू पवार, शेषराव गोयते व सुरेश कोठे को मंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा घनश्याम मोयर (कोषाध्यक्ष), रूदेश धर्माधिकारी (सह-कोषाध्यक्ष), हेमराज कोरडे (कार्यालय मंत्री), सुनील पोतरे (मीडिया प्रभारी) अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्रीराज्य नाना मोहोड, जिला महामंत्री देवेन्द्र गायकवाड,दीपक कामडे, खेमराज सोनेकर,रामेश्वर खोडे, पांढुर्णा नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश बंटी छागानी नामदेव पालआदि थे।

नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान: जुन्नारदेव में जनजागरूकता की शुरुआत, 30 जुलाई तक चलेंगे कार्यक्रम

जुन्नारदेव : मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित #नशे से दूरी है जरूरी 2.0# जनजागरूकता अभियान के तहत मंगलवार को जुन्नारदेव थाना परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक संचालित होगा, जिसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति समाज को जागरूक करना तथा अपराधों की रोकथाम के लिए जनसहभागिता को बढ़ावा देना है।पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे एवं एसडीओपी सोनम पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ज्योति मसराम के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नशामुक्त समाज के निर्माण में पुलिस और नागरिकों की साझा जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया गया। उक्त कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह का सीधा प्रसारण देखा गया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन को उपस्थित पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जनसहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

सरपंच संगठन पहुंचा एसडीएम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन, बोरगांव पंचायत का विवाद पहुंचा सौंसर

हरिभूमि न्यूज ⏭ सौंसर

अनुविभाग क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के दौरान जनप्रतिनिधियों पर हो रहे हमले की घटनाओं को लेकर सरपंच संगठन ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। इस संबंध में मंगलवार को सभी पंचो ओर सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम सौसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है।

वहीं अब ग्राम पंचायत बोरगांव में शासकीय निर्माण कार्य के दौरान हुए विवाद ने तुल पकड़ लिया है। मामले को लेकर सरपंच संगठन ने विवाद करने वाले उपद्रवी तत्व पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कि है। सरपंच संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि दो दिन पूर्व बोरगांव में पंचायत द्वारा नाली निर्माण के दौरान विवाद हो गया था। सरपंच संगठन के खैरीतायगांव सरपंच चंद्रशेखर कहाते,बोरगांव सरपंच पंकज दातारकर,सरपंच सूर्यभान चिकटे ने मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में बताया कि वर्तमान समय मेंअनेक ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के दौरान सरपंच,पंच एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता और विवाद की घटनाएं हो रही है। पंचायत में निर्माण कार्य के दौरान कुछ असामाजिक तत्व शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार एवं हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं।

गंदगी और बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर वार्डवासी

हरिभूमि न्यूज ⏭ परासिया

नगर पालिका वार्ड 21 में रहने वाला श्रीवास्तव परिवार गंदगी और बदबू के बीच जीवन जीने को मजबूर है । परिवार की महिला के द्वारा जिला कलेक्टर , एसडीएम और सीएम हेल्पलाइन 181 में आवेदन के बावजूद कार्रवाई न होने से जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं ।

परासिया नगर पालिका क्षेत्र में एक महिला अपने घर में नाली का गंदा पानी घुसने की समस्या से लगातार परेशान है और न्याय पाने के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है । महिला ने जिला कलेक्टर , जिला प्रशासन , एसडीएम , तहसीलदार और सीएम हेल्पलाइन 181 पर लिखित शिकायत दर्ज कराई , लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई ।महिला का आरोप है , कि जिस वार्ड में यह समस्या बनी हुई है , वहां के कुछ लोगों का परासिया नगर पालिका अध्यक्ष से जुड़े के कारण शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा । पीड़िता का कहना है , कि कई बार आवेदन देने और गुहार लगाने के बाद भी नाली की सफाई , निकासी व्यवस्था सुधारने या जलभराव रोकने के लिए कोई स्थायी कदम नहीं उठाया गया ।इस लापरवाही से महिला और उसका परिवार नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर है । घर में गंदा पानी घुसने से बदबू , संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है , जबकि बरसात के मौसम में परेशानी और गहरा गई है । स्थानीय लोगों का कहना है , कि अगर प्रशासन समय रहते सुनवाई करता, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती ।सबसे बड़ा सवाल यह है , कि जब शिकायत लिखित रूप में दी जा चुकी है , सीएम हेल्पलाइन पर भी मामला दर्ज है और प्रशासन को पूरी जानकारी है , तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ।

क्या जिला प्रशासन ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी हैं , या शिकायतकर्ता को सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया है । यही वजह है , कि अब यह मामला परासिया से लेकर छिंदवाड़ा तक प्रशासनिक निष्क्रियता का प्रतीक बनता जा रहा है ।पीड़िता का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला, तो वह आगे भी शिकायत और कानूनी रास्ते अपनाएगी। लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी मांग सिर्फ इतनी है कि उसके घर में घुस रहा गंदा पानी रोका जाए और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले ।

जवाबदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते सिंगोड़ी स्थित शौचालय बना शोभा की सुपारी

सिंगोड़ी: विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगोड़ी में शौचालय की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। एक ओर बस स्टैंड क्षेत्र में शौचालय की मांग सालों से की जा रही है, दूसरी ओर पूर्व में बना नव निर्मित शौचालय पिछले साल से रिबिन काटने का इंतजार कर रहा है वही बकरी बाजार के सार्वजनिक शौचालय में कई सालो से ताला लगने से वह शोभा की सुपारी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय पंचायत की उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही के चलते ग्रामीणों और किसानों एवं यात्रियों सहित अन्य नागरिकों को शौच क्रिया करने शर्मसार होना पड़ रहा है वह जरूरत पर सड़क किनारे या खड़े वाहनों साइट पर क्रिया को कर रहे है। वही आगे बताया गया कि एक वर्ष पहले पशु चिकित्सालय के सामने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। लेकिन आज तक उसे शुरू नहीं किया गया। शौचालय बंद पड़े होने से वहां गंदगी और अव्यवस्था फैल रही है। इतना ही नहीं, हाट-बाजार क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़े पुराने शौचालय को भी चालू करने की मांग ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। लेकिन पंचायत सहित अन्य लोग इस भारी समस्या की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहे है।

3 दिन में उखड़ी सड़क के बाद हरकत में विधायक

जनपद पंचायत में विशेष बैठक विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त

कटंगी। विकास के नाम पर हो रहे लीपापोती और भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जनप्रतिनिधि खुद मैदान में उतर आए हैं। सोमवार की शाम जनपद पंचायत कटंगी परिसर में विधायक गौरव सिंह पारधी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की वजह बनी थी हमारी ही खबर- परसवाड़ाघाट में राज्य वित्त आयोग की 11.99 लाख की सीसी सड़क 3 दिन में उखड़ गई। इस खबर के प्रकाशित होते ही विधायक ने मामले को गंभीरता से लिया और पूरे विकासखंड में चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए सभी जिम्मेदारों को तलब किया। शाम 5 बजे शुरू हुई इस बैठक में जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी, सभी उपयंत्री, विकासखंड के तमाम ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक मौजूद रहे। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक की शुरुआत में ही विधायक गौरव सिंह पारधी ने परसवाड़ाघाट वाली सड़क का जिक्र किया। उन्होंने कहा, विशेष प्रयासों के बाद राज्य वित्त आयोग की राशि मिल पाती है। अगर 11 लाख 99 हजार की सड़क 3 दिन में उखड़ जाएगी तो ये जनता के साथ धोखा है। ठेकेदार, सचिव और उपयंत्री सबकी जवाबदेही तय होगी। विधायक ने उपयंत्रियों को कड़ी हिदायत दी कि अब से निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। सड़क, नाली, भवन कोई भी काम हो, उसकी गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने भी अपने मातहत कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर किया जाए। बैठक के दौरान कई ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिवों ने हर घर नल जल योजना को लेकर अपनी पीड़ा रखी। सरपंचों का आरोप था कि कई गांवों में योजना तो कागजों पर पूरी हो गई है, लेकिन आज तक घरों में पानी नहीं पहुंचा। कुछ जगह पाइपलाइन बिछी है लेकिन मोटर, टंकी और वाल्व जैसे उपकरण या तो लगाए ही नहीं गए या फिर बेहद घटिया क्वालिटी के लगाए गए हैं, जो 1 महीने में ही खराब हो गए। इस शिकायत को सुनते ही विधायक ने तत्काल आगामी गुरुवार को एक विशेष बैठक बुलाने का निर्णय लिया। इसमें प्रभावित ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारी शामिल होंगे। विधायक ने कहा, पानी पीने की मूलभूत सुविधा है। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

फर्जी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों से पंचायतें परेशान-

बैठक में एक अनोखी समस्या भी सामने आई। कई सरपंचों और सचिवों ने बताया कि कुछ फर्जी पत्रकारों द्वारा ग्राम पंचायतों के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायतें की जा रही हैं। सचिवों ने कहा कि बिना जांच के ही इन शिकायतों पर नोटिस आ जाते हैं, जिससे पंचायत का कामकाज ठप हो जाता है और अनावश्यक दबाव बनता है। इस पर विधायक ने कहा कि गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने कहा कि पहली बार यह शिकायत उनके संज्ञान में लाई गई है। उन्होंने सीईओ को निर्देश दिए कि ऐसी शिकायतों का सत्यापन पहले पंचायत स्तर पर हो, उसके बाद ही जवाब मांगा जाए। जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए, लेकिन झूठ बोलकर सिस्टम को बदनाम करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा।

आंगनवाड़ी भवनों पर विशेष फोकस-

बैठक का एक अहम एजेंडा आंगनवाड़ी केंद्रों की बदहाली भी रहा। विधायक ने निर्देश दिए कि पूरे विकासखंड में जर्जर, किराए के भवन में चल रही और भवनविहीन आंगनवाड़ियों की सूची तत्काल बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने खासतौर पर सेलवा, हथौड़ा, चिकमारा, पौनिया और तिरोड़ी' क्षेत्र के सरपंचों से कहा कि उनके गांवों के आसपास खदानें संचालित हो रही हैं। इन खनन कंपनियों से आंगनवाड़ी भवन बनवाने' की दिशा में चर्चा करें। खदान मालिक उनके यहां से मुनाफा कमा रहे हैं। बच्चों के लिए एक पक्का भवन तो दे ही सकते हैं। सरपंच इस मामले में पहल करें, प्रशासन और मैं व्यक्तिगत तौर पर मदद करूंगा। इस पर सीईओ ने बताया कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) के तहत खदानों के 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में 'बेसलाइन सर्वे' कराया जा रहा है। सर्वे के बाद उन गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता से दिया जाएगा।

स्कूल भवनों का निर्माण पंचायतों को देने की सिफारिश-

बैठक में शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विधायक ने बताया कि कुछ गांवों में नए स्कूल भवनों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने सरकार से सिफारिश की है कि इन भवनों के निर्माण कार्य पंचायतों को ही दिए जाएं। विधायक का तर्क था कि पंचायतें स्थानीय हैं, वह बेहतर निगरानी कर सकती हैं और इससे गांव के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने पंचायतों को भी चेताया कि अगर काम पंचायत को मिला तो गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। काम अच्छा होना चाहिए, तभी देंगे।

बैंक खाते खुलवा कर 12 लाख से ज्यादा का लेनदेन

युवाओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग

कटंगी। मंगलवार की दोपहर 03 बजे कटंगी पुलिस थाने में दो अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए और ज्ञापन सौंपने वाले युवाओं से लेकर कथित धार्मिक संगठन के पदाधिकारियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप किया। पूरा मामला कथित धार्मिक संगठन श्रीराम सेना के पदाधिकारियों और सागर कठौते के बीच चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है। सागर कटौते सोशल मीडिया में अकसर अपनी बातों को पूरी बेबाकी से रखते है और यही बात श्रीराम संगठन के पदाधिकारियों को खटक रही है। जिसके चलते 28 जून 2026 को संगठन के पदाधिकारियों ने सागर कटौते के खिलाफ थाने में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी थी। वहीं स्वयं को संगठन का नगर मंत्री बताने वाले विकास सूर्यवंशी ने सागर कटौते को असामाजिक तत्व कहा था। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। सागर कटौते को असामाजिक तत्व कहे जाने से सागर के समर्थकों में गुस्सा दिखाई दिया। उन्होंने मंगलवार 14 जुलाई को सागर कटौते के साथ थाना पहुंचकर पुलिस के सामने संगठन से जुड़े लोगों को पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने अपना बचाव करते हुए श्रीराम जनसेना अंतरराष्ट्रीय महासंघ के बैनर पर ज्ञापन सौंपा और सागर कटौते के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सागर कटौते और क्षेत्र भर से आए युवाओं ने श्रीराम सेना नामक अपंजीकृत संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। युवाओं ने आरोप लगाया कि कथित धार्मिक संगठन के पदाधिकारी आस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे है। भोले-भाले युवाओं के बैंक खाते खुलवाकर अवैध आर्थिक लेनदेन किया गया है और सागर कटौते जैसे जागरूक युवा की सामाजिक छवि धूमिल करने के कुंठित प्रयास किया गया है। विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी जो स्वयं को श्रीराम सेना का नगर अध्यक्ष और नगर मंत्री बताते हैं। वह समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे है। सागर कटौते के साथ ज्ञापन सौंपने आए युवक भावेश नेवारे और आयुष नेवारे ने भी आज पुलिस के सामने फिर एक बार अपनी व्यथा सुनवाई। इन युवकों ने आरोप लगाया कि विकास सूर्यवंशी और सागर पंजवानी भगवान प्रभु श्रीराम की आस्था का हवाला देकर भोले-भाले आर्थिक रूप से पीड़ित युवाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उनके साथ धोखा कर रहे है। अखाड़े के नाम पर चंदा आने की बात कहकर युवाओं से एचडीएफसी बैंक शाखा कटंगी में खाते खुलवाए गए। बाद में खाताधारकों की जानकारी के बिना उन खातों में सागर पंजवानी ने अवैध आर्थिक लेन-देन किया है। आयुष और भावेश ने बताया कि बैंक खाता खुलने के बाद सागर ही अपने बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड रखता है। आयुष नेवारे ने बताया कि 3 अप्रैल 2024 से 29 मई 2025 तक उसके नाम से खुले बैंक खाते में कुल 9 लाख 40 हजार रुपये का लेनदेन हुआ। इसी तरह भावेश नेवारे के खाते से 22 अप्रैल 2024 से 06 अप्रैल 2026 तक 3 लाख 13 हजार रुपये का लेनदेन बिना उनकी जानकारी के हुआ। आयुष नेवारे ने बताया कि जब उसके द्वारा खाते में हो रहे लेनदेन की जानकारी मांगी तो सागर पंजवानी ने जानकारी नहीं दी और बात छिपाने का दबाव बनाया।

कोपे के घने जंगल में मिला युवक का शव

शव के पास से शराब और पानी की बोतल बरामद

हत्या की जांच में जुटी वारासिवनी पुलिस

हरिभूमि न्यूज़ वारासिवनी। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम पंचायत कोपे के घने जंगल में मंगलवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर वारासिवनी पुलिस मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ में जुट गई। जिसके पश्चात मृतक युवक की पहचान ग्राम डोंगरिया निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र शरणागत के रूप में हुई है। मृतक के आसपास से शराब और पानी की बोतल बरामद की गई है। वहीं मृतक के कान से खून और गले पर काले निशान दिखाई दे रहे है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक किसी के साथ जंगल में शराब पीने आया होगा और वाद विवाद के बाद युवक की गला दबा कर हत्या की गई होगी। बताया जा रहा है कि मृतक सोमवार की दोपहर से अपने घर से लापता था।जिसकी तलाश परिवार द्वारा की जा रही थी। वहीं बालाघाट से एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और वहीं पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

एसडीओपी अभिषेक चौधरी और एफएसएल की टीम ने बारीकी से घटना स्थल की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अभिषेक चौधरी,थाना प्रभारी अनूप कुमार उईके और बालाघाट एफएसएल की टीम ग्राम कोपे के जंगल में पहुंची और शव के चारो ओर कुछ दूरी को सील कर दिया गया।जिससे पुलिस को मिलने वाले सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। वहीं डॉग स्कॉड की मदद से पुलिस आरोपी की पहचान में जुट गई है।

कुछ दिनों से गांव में किसी के साथ चल रहा है विवाद- रीना शरणागत

मृतक की पत्नी रीना शरणागत ने बताया कि सोमवार की दोपहर 12 बजे से वह घर पर नहीं थे। किसी पुलिस वाले के साथ गए थे।जिसने कहा था कि आपके ऊपर केस चल रहा है। साइन करने चलो, तो वह उसके साथ चले गए थे और आने के बाद सरपंच के घर भी उनसे मिलने गए थे। उसके बाद वापस घर आए ही नहीं।फिर मुझे मंगलवार की सुबह 11 बजे कोपे निवासी बुआ के बेटे ने बताया कि भैया का शव जंगल में मिला है। उसके बाद मै यहां आई। गांव में ही पहले किसी के साथ झगड़े का विवाद चल रहा है।अब इनकी हत्या कैसे हुई?किसने किया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कुछ दिनों से मैं अपने रिश्तेदार के घर बाहर गई थी। कल मुझे मेरे पति ने कॉल किए थे कि तू गांव आ जा, तो मैंने उन्हें कहा था कि 2-3 बजे तक आ जाऊंगी। मै घर आई, तो वे घर में नहीं थे।और रात भर नहीं आए।

खबर संक्षेप

कुकिंग कंपटीशन संपन्न, रसोईयों ने किया अपनी पाक कला का प्रदर्शन

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय कुकिंग कंपटीशन जनपद पंचायत सिवनी के सभा कक्ष में आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में शासकीय शालाओं में भोजन बनाने वाले 38 रसोइयों ने भाग लिया । कार्यक्रम का उद्देश्य भोजन में गुणवत्ता सुधार करना,पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन तैयार करने की जानकारी देना एवं रसोइयों के पाक कौशल का विकास करना था। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने शालाओं में परोसे जाने वाले मीनू के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यंजन स्वयं अपने घर से तैयार कर ले गए जिसे कार्यक्रम स्थल में बहुत ही सलीके से अपनी -अपनी थालियों में प्रदर्शित किया गया। किसी ने मक्के की रोटी तो किसी ने अंकुरित अनाजों से अपनी थाली को सजाया ।

मठ कन्या विद्यालय में मिशन शक्ति अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

छात्राओं को साइबर सुरक्षा एवं महिला सहायता सेवाओं की दी जानकारी

हरिभूमि न्यूज सिवनी।कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री मनोज लारोकर के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अंतर्गत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ एवं हब फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन योजना के तहत जिले में लगातार जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी क्रम में सोमवार को मठ कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवनी में प्रशासक सुश्री ईशा बाल्मीक के मार्गदर्शन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर श्रीमती वर्षा बैंस ने छात्राओं को वन स्टॉप सेंटर की कार्यप्रणाली, उपलब्ध सेवाओं तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर 1098, 181, 112 एवं 1930 की विस्तृत जानकारी दी।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम एवं स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

हरिभूमि न्यूज सिवनी। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री उद्यम योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवक - युवतियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के सेवा, उद्योग एवं व्यवसाय संबंधी प्रकल्पों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों योजनाओं में इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा।

मोहगांव सड़क पर एनएच 44 से अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों ने मांगा एक सप्ताह का समय

एनएचएआई की कार्रवाई से पहले करीब 40 दुकानदारों ने दिया लिखित आश्वासन, 21 जुलाई से हटेगा अतिक्रमण

हरिभूमि न्यूज सिवनी।

नेशनल हाईवे-44 स्थित मोहगांव सडक़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई फिलहाल एक सप्ताह के लिए टाल दी गई है। सोमवार को एनएचएआई की टीम जेसीबी, डंपर एवं अन्य संसाधनों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। बताया गया कि हाईवे की भूमि पर करीब 40 दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। कार्रवाई शुरू होने से पहले दुकानदारों ने अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर सात दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया कि वे 20 जुलाई 2026 तक स्वयं अपना अतिक्रमण हटा देंगे। मामले में कुरई जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह भाटिया के हस्तक्षेप और निवेदन के बाद एनएचएआई अधिकारियों ने दुकानदारों को 7 दिनों की मोहलत देने पर सहमति जताई। दुकानदारों द्वारा दिए गए लिखित आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो 21 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दुकानों में रखे सामान की पूरी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदारों की होगी। एनएचएआई ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के बाद बिना किसी अतिरिक्त सूचना के कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया है।

चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कार्यवाही लगातार जारी

कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं मिलावटखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से मंगलवार को सिवनी शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर त्वरित स्पॉट परीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की गई।

हरिभूमि न्यूज सिवनी।

विद्यार्थियों को मिलावट की पहचान की दी जानकारी

कार्रवाई के दौरान यादव मंगोड़ा सेंटर (संचालक मुकेश यादव) से मंगोड़े, एल.डी. मार्ट से फ्रेम्स तथा श्री साई जूस कॉर्नर से एप्पल जूस के नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए। साथ ही मौके पर खाद्य पदार्थों का स्पॉट परीक्षण कर उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया गया।
इसी क्रम में पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिवनी में विद्यार्थियों को चलित खाद्य प्रयोगशाला का प्रदर्शन कर खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान के लिए किए जाने वाले स्पॉट परीक्षणों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने की रासायनिक विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग के प्रति जागरूक किया।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 13 जुलाई 2026 को नटराज स्वीट्स, कचहरी चौक का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समोसे का नमूना जांच हेतु लिया गया। प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं पाए जाने पर खाद्य कारोबारकर्ता को सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में आवश्यक सुधार नहीं किए गए अथवा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन जारी रहा, तो संबंधित खाद्य प्रतिष्ठान के खाद्य लाइसेंस के निलंबन सहित नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलेभर में निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

लगातार उत्कृष्ट पुलिस कार्य, जनसंपर्क और कानून व्यवस्था में बेहतर योगदान के लिए मिली पदोन्नति

जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सी.के. सिरामे को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर पदोन्नत किए जाने की जानकारी सामने आई है।

हरिभूमि न्यूज सिवनी। लगभग तीन वर्षों से अधिक समय तक लखनवाड़ा थाना प्रभारी के रूप में सेवाएं देते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ आमजन के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, जनसुनवाई, सामुदायिक पुलिसिंग तथा लोगों से मधुर व्यवहार के माध्यम से पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत किया। उनके कार्यों की क्षेत्र में लगातार सराहना होती रही। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीएसपी पद पर पदोन्नति मिलने के बाद लखनवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारियों एवं नागरिकों ने श्री सिरामे को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

आज गौघाट धाम में होगा वृक्षारोपण, प्रकृति प्रेमियों से सहभागिता की अपील

हरिभूमि न्यूज सिवनी। कान्हीवाड़ा। प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला वृक्षारोपण कार्यक्रम इस वर्ष भी आज 15 जुलाई को सुबह 8 बजे कान्हीवाड़ा के समीप स्थित धार्मिक स्थल गौघाट धाम में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सभी प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमियों से उपस्थित होकर पौधरोपण अभियान में सहभागिता करने की अपील की गई है। गौघाट यज्ञ समिति के संरक्षक श्रीराम ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि गौघाट धाम में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 29 मई 2017 को हुई थी, जो पिछले नौ वर्षों से निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि वे महापुरुषों की जयंती, धार्मिक पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस तथा अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिवस जैसे विशेष अवसरों पर नियमित रूप से पौधरोपण करते आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 15 जुलाई को गौघाट धाम में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

दीपक जयहिंद टीम ने ग्राम बकौड़ी की जर्जर सड़क और श्मशान घाट की बदहाल स्थिति को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दीपक जयहिंद टीम सिवनी के संस्थापक दीपक डेहरिया के नेतृत्व में ग्राम बकौड़ी (ग्राम पंचायत जमुनिया, थाना बंडोल, तहसील एवं जिला सिवनी) की वर्षों से जर्जर सडक़ तथा श्मशान घाट में टीन शेड जैसी मूलभूत सुविधा के अभाव को लेकर कलेक्टर सिवनी को ज्ञापन सौंपा गया।

हरिभूमि न्यूज सिवनी।

ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम की मुख्य सडक़ लंबे समय से अत्यंत खराब स्थिति में है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं, मरीजों, किसानों तथा आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा, ग्राम के श्मशान घाट में टीन शेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण वर्षा एवं तेज धूप के समय अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को गंभीर असुविधा झेलनी पड़ती है। टीम ने इसे संवेदनशील एवं जनहित का विषय बताते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है।
दीपक जयहिंद टीम के संस्थापक दीपक डेहरिया ने कहा कि सडक़, श्मशान घाट, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार हैं। प्रशासन को ग्रामीणों की समस्याओं का स्थायी समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्रामीणों की समस्याएं और अधिक गंभीर हो सकती हैं।
टीम ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम बकौड़ी की सडक़ का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए, आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल कराया जाए तथा श्मशान घाट में टीन शेड का निर्माण कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
टीम ने विश्वास जताया कि जिला प्रशासन जनहित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करेगा, जिससे ग्रामवासियों को राहत मिल सके।

देशव्यापी आह्वान के तहत 15 से 17 जुलाई तक सांकेतिक आंदोलन

मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन और शासकीय कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी

हरिभूमि न्यूज सिवनी।

मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सिवनी जिले के समस्त पटवारी बुधवार से तीन दिवसीय सामूहिक अवकाश पर चले गए। जिला अध्यक्ष सुदेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जिले की सभी तहसीलों के पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन एवं अवकाश पत्र सौंपकर वर्षों से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की।पटवारी संघ का कहना है कि लंबे समय से उनकी न्यायोचित मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे पूरे संवर्ग में असंतोष व्याप्त है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शासन ने समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और अधिक व्यापक बनाया जाएगा।
ज्ञापन में संघ ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें कैडर रिव्यू लागू कर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ देना, वर्ष 2018 के बाद से लंबित नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा का आयोजन, राजस्व प्रकरणों में कार्यरत पटवारियों को जज प्रोटेक्शन एक्ट का संरक्षण प्रदान करना, विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सर्वे कार्यों के लंबित मानदेय का भुगतान तथा स्थानांतरण नीति-2026 के विपरीत किए गए स्थानांतरणों को निरस्त करना शामिल है।
पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 से 17 जुलाई तक का यह सामूहिक अवकाश सांकेतिक आंदोलन है। यदि इस अवधि के बाद भी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर के पटवारी शासकीय योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों का बहिष्कार करते हुए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।

धूमधाम और भावुक क्षणों के बीच संपन्न हुआ विदाई समारोह, हेमंत बिसेन को दी गई आत्मीय विदाई

केवलारी/ (सिवनी)। स्थानीय कृषि उपज मण्डी में पदस्थ हेमंत बिसेन सहायक ग्रेड 3 के सेवानिवृत्त होने पर एक भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहयोगियों और अतिथियों ने उनके सेवाकाल की सराहना करते हुए उन्हें अत्यंत भावभीनी विदाई दी।

कार्यक्रम की शुरुआत

मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके पश्चात संस्था के सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विदाई ले रहे हेमंत बिसेन का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिह्न और पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत व सम्मान किया गया।

वक्ताओं ने सराहा उत्कृष्ट कार्यकाल

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं में मंडी सचिव राजेश ऊईके, संजीव अवधिया ने सेवाकाल की खुलकर प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि इनका संपूर्ण कार्यकाल अत्यंत सराहनीय, कर्तव्यनिष्ठ और प्रेरणादायक रहा है। इन्होंने हमेशा अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन किया और संकट के समय भी धैर्य से काम लिया। संस्था के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सहकर्मियों ने उनके साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए कहा कि वे न केवल एक बेहतरीन सहकर्मी रहे, बल्कि हमेशा एक

मार्गदर्शक और अभिभावक की भूमिका में भी नजर आए। अपनी विदाई की इस बेला पर हेमंत बिसेन ने अत्यंत भावुक मन से सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस संस्थान से उन्हें जो मान-सम्मान और स्नेह मिला है, उसे वे जीवनभर नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने सहकर्मियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से राजेश ऊईके मंडी सचिव। संजीव अवधिया अतीक खान कल्लू अग्निहोत्री। दिलेश मंवरे , सौरभ प्रधान अकाउंटेंट ब्रजहरी बघेल, योगिता ऊईके कौशल तिवारी आदि अधिकारी,कर्मचारियों की उपस्थिति में हेमंत बिसेन सहायक ग्रेड 3 को शाल श्री फल भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। कृषि उपज मंडी विभाग के समस्त कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। मंच का सफल संचालन संचालक अतीक खान द्वारा किया गया।

शहर के स्पीड ब्रेकरों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए पेंट किया जावे-भाकपा

हरिभूमि न्यूज सिवनी। नगर पालिका सिवनी द्वारा सडक़ दुर्घटनाओं से बचने के लिए शहर की सडक़ों पर जगह-जगह स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं परंतु इस पर पेंट नहीं करने से वे वाहन चालकों को एकाएक दिखाई नहीं देते हैं जिससे वहां पर बैठने वाले लोग डगमगा जाते हैं जिससे सडक़ दुर्घटनाएं बढऩे की संभावनाएं बढ़ जाती है। अतः नगर पालिका प्रशासन एवं जिला प्रशासन से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ओम प्रकाश बोर्ड सहित डीडी वासनिक डॉ बी सी ओके राजेंद्र जैसवाल तीरथ प्रसाद गजभिए किरण प्रकाश राहुल कुमार यीशु प्रकाश गेंदलाल भलावी धनीराम बंडेवार इरफान पठान पवन कुमार सनोडिया अंगद सिंह बघेल आदि ने नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि जहां-जहां स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं उन सभी पर सफेद पेंट करके उन्हें ऐसा बनाया जावे की वह हर वाहन चालक को स्पष्ट रूप से दिखाई दे जिससे संभावित सिवनी शहर में सडक़ दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

जब व्यवस्था सोती रही, तब ग्रामीणों ने संभाली जिम्मेदारी

बच्चों की सुरक्षा के लिए चक्की खमरिया-सिमरिया मार्ग को श्रमदान से किया गड्ढा मुक्त, किसानों, स्कूल प्रबंधन और पंचायत ने मिलकर पेश की मिसाल

हरिभूमि न्यूज सिवनी।

कुरई जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चक्कीखमरिया से सिमरिया तक जाने वाले जर्जर मार्ग पर प्रशासनिक उदासीनता के बीच ग्रामीणों ने जनसहभागिता की मिसाल पेश करते हुए श्रमदान से सडक़ को गड्ढामुक्त कर दिया। प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, किसान और ग्रामीण इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। सडक़ पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता था और बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से सडक़ की मरम्मत नहीं होने और संबंधित विभागों की ओर से कोई पहल नहीं किए जाने पर चक्की खमरिया के किसानों ने स्वयं आगे बढक़र अपने खर्च पर ट्रैक्टर लगाकर सडक़ सुधार का कार्य शुरू किया। इस अभियान में सिमरिया ग्राम पंचायत की सरपंच ने जेसीबी मशीन उपलब्ध कराई, जिससे मरम्मत कार्य तेजी से पूरा हो सका। जनहित के इस कार्य में सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य विनोद चौरसिया ने आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अखिलेश तिवारी ने भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सहयोग दिया। चक्की खमरिया ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी अपना निजी ट्रैक्टर लगाकर इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन और जनप्रतिनिधि समय पर सडक़ की मरम्मत कराते तो उन्हें स्वयं यह जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। बच्चों की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने संसाधनों और श्रम से सडक़ को चलने योग्य बनाया।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि चक्की खमरिया-सिमरिया मार्ग का शीघ्र स्थायी निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में बच्चों, किसानों और आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उनका कहना है कि जनसहभागिता से फिलहाल समस्या का अस्थायी समाधान हो गया है, लेकिन स्थायी राहत केवल गुणवत्तापूर्ण सडक़ निर्माण से ही मिलेगी।
ग्रामीणों का संदेशःबच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है। जब जिम्मेदार विभाग आगे नहीं आए, तब गांव ने स्वयं जिम्मेदारी निभाई। अब प्रशासन को स्थायी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

दादा गुरु भैया जी सरकार के कर-कमलों से हुआ नर्मदा सेवा आश्रम का भूमि पूजन

कहानी। नगर में नर्मदा सेवा समिति के प्रस्तावित नर्मदा सेवा आश्रम निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। लगभग दो वर्ष पूर्व कहानी निवासी नेमा परिवार द्वारा नर्मदा सेवा समिति को दान स्वरूप प्रदान की गई भूमि एवं कच्चे भवन पर मंगलवार को दादा गुरु भैया जी सरकार के कर-कमलों से विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। जानकारी के अनुसार, नर्मदा सेवा समिति लंबे समय से इस भूमि पर नर्मदा सेवा आश्रम के निर्माण की योजना पर कार्य कर रही थी। इसी उद्देश्य से समिति ने दादा गुरु भैया जी सरकार से भूमि पूजन कराने का आग्रह किया था। अपने पूर्व निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान के तहत पलारी जाते समय भैया जी सरकार ने समिति के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहानी पहुंचकर भूमि पूजन संपन्न कराया।
दादा गुरु के नगर आगमन पर नगर सीमा से ही ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी एवं नर्मदे हर के जयघोष के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ शोभायात्रा मुख्य मार्ग से होती हुई निर्माण स्थल तक पहुंची, जहां विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमि पूजन कराया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, नर्मदा सेवा समिति के पदाधिकारी,

सामाजिक कार्यकर्ता एवं नगरवासी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा। नर्मदा सेवा समिति ने बताया कि भूमि पूजन के साथ ही आश्रम निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शीघ्र ही दान में प्राप्त भूमि पर नर्मदा सेवा आश्रम का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। समिति का उद्देश्य इस आश्रम को नर्मदा परिक्रमा यात्रियों, संत-महात्माओं एवं धार्मिक-सामाजिक सेवा कार्यों का प्रमुख केंद्र बनाना है।

हरिभूमि

सतपुड़ा भूमि

[तिरोड़ी | बोनकटा | कंटगी | बैहर | वारासिवनी | हटा]

जबलपुर, बुधवार 15 जुलाई 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

कासनाला पुल निर्माण के लिए तीन किसानों की भूमि क्रय प्रस्तावित, 15 दिन में मांगी गई आपत्तियां

वारासिवनी। तहसील के अंतर्गत बुदबुदा-नदीटोला मार्ग स्थित कासनाला में जलमग्नीय पुल निर्माण के लिए तीन भूमिस्वामियों की कुल 0.279 हेक्टेयर भूमि क्रय किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भूमि लोक निर्माण विभाग के सेतु निर्माण संभाग, बालाघाट के पक्ष में क्रय की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वह सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्ताव के अनुसार बुदबुदा निवासी झामसिंह पिता रामलाल की 0.129 हेक्टेयर, रमेश पिता तिलकचंद की 0.089 हेक्टेयर तथा राधेश्याम पिता रामलाल की 0.061 हेक्टेयर भूमि पुल निर्माण कार्य के लिए क्रय किए जाने का प्रस्ताव है। प्रशासन ने संबंधित पक्षों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने दावा-आपत्तियां प्रस्तुत करने का आग्रह किया है।

जिला न्यायालय परिसर सहित छह न्यायालय परिसरों की सफाई एवं उद्यान रख रखाव के लिए निविदाएं आमंत्रित

बालाघाट। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा जिला न्यायालय परिसर, परिवार न्यायालय परिसर बालाघाट तथा तहसील न्यायालय वारासिवनी, बैहर, कटंगी एवं लांजी परिसरों में यांत्रिक सफाई (मैकेनाइज्ड क्लीनिंग) एवं उद्यान/पौधरोपण के रखरखाव कार्य के लिए प्रतिष्ठित एवं अधिकृत एजेंसियों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

निविदाएं मध्य प्रदेश शासन के ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 सायं 5:00 बजे निर्धारित की गई है। प्राप्त निविदाओं को 25 अगस्त 2026 को सायं 5:00 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय, बालाघाट में खोला जाएगा। निविदा प्रक्रिया से संबंधित प्री-बिड बैठक 13 अगस्त 2026 को सायं 5:00 बजे जिला न्यायालय, बालाघाट में आयोजित होगी, जिसमें इच्छुक एजेंसियां भाग लेकर निविदा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगी।

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं अन्य आवश्यक जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश शासन के ई-टेंडर पोर्टल तथा जिला न्यायालय, बालाघाट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। इच्छुक एवं पात्र एजेंसियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने का आग्रह किया गया है।

डेढ़ साल में उखड़ गई करोड़ों की सड़क, पुलिया पर बना 'मौत का गड्ढा' आखिर किस हादसे का इंतजार कर रहे जिम्मेदार?

हरिभूमि न्यूज़ लांजी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत करोड़ों रुपये की लागत से बनाई गई दहेगांव-कारंजा मार्ग की सड़क अब निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सड़क बने अभी लगभग डेढ़ वर्ष ही बीता है, लेकिन कारंजा पुलिया के बीचों-बीच बना विशाल गड्ढा राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिया की सतह धंस चुकी है, यह दृश्य जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी की कार्यशैली पर करारा तमाचा माना जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की खुलकर अनदेखी की गई। परिणाम यह है कि नई सड़क इतनी जल्दी जर्जर हो गई। लोगों का कहना है कि कई बार इस गड्ढे के कारण बाइक सवार और छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही ठेकेदार ने मरम्मत की कोई पहल की। पंचायत स्तर पर भी सरपंच और सचिव की उदासीनता से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।

क्या किसी की जान जाने के बाद खुलेगी प्रशासन की नींद?

बरसात के मौसम में यह गड्ढा और भी खतरनाक हो गया है। पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और ठेकेदार की कथित मिलीभगत के कारण घटिया निर्माण पर पर्दा डाला जा रहा है। यदि निर्माण कार्य गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप हुआ होता तो इतनी कम अवधि में सड़क इस हालत में नहीं पहुंचती। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल गड्ढे की मरम्मत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब जागेगा- किसी निर्दोष की जान जाने से पहले या फिर किसी बड़े हादसे के बाद? ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल तकनीकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई तथा पुलिया की शीघ्र मरम्मत की मांग की है।

बेदखली से पहले पुनर्वास की मांग तेज, गरीब परिवारों ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार

बालाघाट। शहर के आकाशवाणी और पॉवर हाउस के बीच वर्षों से निवास कर रहे दर्जनों परिवारों पर बेदखली की कार्रवाई की आशंका गहराने के बाद विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। मंगलवार को प्रभावित रहवासी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वैकल्पिक एवं सम्मानजनक पुनर्वास की मांग की। रहवासियों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। हाईकोर्ट के निदेर्शों के बाद प्रशासन द्वारा हटाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से उनके सामने आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी प्रभावित परिवारों के लिए निःशुल्क और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

प्रशासन की ओर से ढिमरटोला स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में बसाने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन प्रभावित परिवारों ने आर्थिक मजबरी का हवाला देते हुए इसे स्वीकार करने में असमर्थता जताई। उनका कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूर और सीमित आय वाले लोग हैं। ऐसे में एकमुश्त राशि जमा करना और बाद में ऋण की मासिक किस्त चुकाना उनके लिए संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता मनोज पमनानी ने कहा कि वर्षों से बसे गरीब परिवारों को बिना पर्याप्त पुनर्वास व्यवस्था के हटाना सामाजिक न्याय की भावना के विपरीत होगा। उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसा समाधान निकालने की मांग की, जिससे किसी परिवार को बेघर न होना पड़े। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रभावित परिवारों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 17 जुलाई को भोपाल में विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जाएगा।

ईतवारी बाजार में जर्जर दुकान को किया गया ध्वस्त जनसुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका की कार्रवाई

हरिभूमि न्यूज़ बालाघाट। बालाघाट शहर के ईतवारी बाजार क्षेत्र में स्थित एक जर्जर दुकान को मंगलवार, 14 जुलाई को नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से ध्वस्त (डिस्मेंटल) किया गया। यह कार्रवाई पूर्व में जारी किए गए नोटिस के पालन में नगर पालिका के अमले द्वारा की गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सूर्यप्रकाश उके ने बताया कि संबंधित भवन मालिक को जर्जर दुकान को हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था। भवन की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे मशीनों की सहायता से डिस्मेंटल किया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देशानुसार जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी जर्जर भवनों की पहचान की जा रही है, जिनसे जनहानि की आशंका है। चिन्हित भवनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। नगर पालिका बालाघाट ने भवन स्वामियों से भी अपील की है कि यदि उनकी इमारतें जर्जर अवस्था में हैं, तो उन्हें समय रहते सुरक्षित कराएं अथवा स्वयं हटाने की कार्रवाई करें, जिससे आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय नमस्ते दिवस का गरिमामय आयोजन

सफाई मित्रों का किया गया सम्मान एवं पीपीई किट वितरित

हरिभूमि न्यूज़ वारासिवनी। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा संचालित योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम के अंतर्गत सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई मित्र एवं कचरा बिनने वाले सफाई मित्रों को शामिल कर निर्देशानुसार आज 14 जुलाई 2026 को नगर पालिका परिषद वारासिवनी में राष्ट्रीय नमस्ते दिवस का आयोजन गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दादरे, उपयंत्री श्रीमती अंशिका सिंह चौहान , जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर अधिकारी-कर्मचारी एवं सफाई मित्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नमस्ते योजना अंतर्गत पंजीकृत सफाई मित्रों एवं वेस्ट पिकर्स का सम्मान करते हुए उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट तथा पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने सफाई मित्रों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आयोजन के अंतर्गत सफाई मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, शिविर आयोजित किए गए। जिसमें उपस्थित स्वच्छता मित्रों का स्वास्थ परीक्षण मेडिकल ऑफिसर एवं स्टाफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरिता मनोज दादरे ने कहा कि सफाई मित्र हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका सम्मान, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राष्ट्रीय नमस्ते दिवस का उद्देश्य सफाई मित्रों के योगदान का सम्मान करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। श्रीमती अंशिका सिंह चौहान उपयंत्री एवं स्वच्छता नोडल द्वारा कहा गया कि नगर पालिका द्वारा सफाई मित्रों के कल्याण हेतु संचालित सभी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा भविष्य में उनके हित में निरंतर कार्य किए जाएंगे।कार्यक्रम का समापन सभी उपस्थितजनों द्वारा स्वच्छता, सुरक्षित कार्य व्यवहार एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रीमती सरिता मनोज दादरें अध्यक्ष नगर पालिका वारासिवनी, पार्षदगण धर्मेश धरमू जोशी व प्रवीण डोंगरे एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसेडर, मिथलेश बूरडे मनोनीत पार्षद, श्रीमती अंशिका सिंह चौहान उपयंत्री, एनजीओ नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता मित्र उपस्थित रहे।

दिल्ली के पूसा संस्थान में गूंजा कटंगी क्षेत्र का नाम

राष्ट्रीय वृक्ष मित्र संवाद में रखा पर्यावरण और किसानों के मुद्दे

कटंगी। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा में गत दिवस रविवार को आयोजित राष्ट्रीय वृक्ष मित्र संवाद कार्यक्रम में क्षेत्र के ग्राम अगासी के युवा अवलेश पारधी ने बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गरिमामयी उपस्थिति रहे। इस महाअभियान के दौरान अवलेश पारधी ने पूरे देश के सामने पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्षेत्र का विजन और नीतिगत सुझाव रखे। अवलेश पारधी ने मंच से कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, इसके लिए जन-जन को जोड़ना होगा। उन्होंने क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण और जैव विविधता को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र और किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा की। किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। अवलेश पारधी ने चर्चा करते हुए कहा क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद और शुभकामनाओं के बल पर ही मुझे यह अवसर मिला। यह गौरव केवल मेरा नहीं, बल्कि क्षेत्र के और आप सभी राष्ट्र-समर्पित साथियों का है। सृजन और संरक्षण के इस महायज्ञ में आप सभी की शुभेच्छा ही मेरी असली ताकत है। उन्होंने आह्वान किया कि आइए, हम सब मिलकर प्रकृति संरक्षण के इस संकल्प को जन-जन का आंदोलन बनाएं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में हुए इस राष्ट्रीय संवाद का उद्देश्य देशभर के युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक मंच पर लाना था। इसमें देशभर से आए युवा प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं और समाधान साझा किए।

15 से 30 जुलाई तक चलेगा नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान, जनभागीदारी से नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान

बालाघाट। जिले में 15 से 30 जुलाई 2026 तक संचालित होने वाले नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जनजागरूकता अभियान के सफल संचालन को लेकर मंगलवार 14 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भोपाल से लाइव संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा गया।

बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर श्री जी.एस. धुर्वे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री निहित उपाध्याय, डीएसपी (आईजी कार्यालय) श्री राजाराम धाकड़, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर, पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य श्री मौसम बिसेन, एसडीएम श्री गोपाल सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि, सामाजिक एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ₹नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा जनआंदोलन है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नशामुक्त मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार डकैतों और नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, उसी तरह अब हर प्रकार के नशे पर रोक लगाने के लिए ड्रग माफिया, तस्करों और नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण अभियान है, जिसकी सफलता के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं तथा आम नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है।

बैठक की शुरुआत में पुलिस विभाग द्वारा अभियान की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। अधिकारियों को अभियान के चार प्रमुख आयाम—इन्फोर्समेंट एवं इंटेलिजेंस ऑपरेशन, प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक ड्रग्स कंट्रोल, डिमांड एवं हार्म रिडक्शन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग एवं कोऑर्डिनेशन—की जानकारी दी गई। साथ ही पिछले अभियान की उपलब्धियों की समीक्षा कर इस वर्ष इसे और अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने कहा कि ₹नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0₹ केवल पुलिस विभाग का अभियान नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागों से अपने-अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों का प्रभावी उपयोग करते हुए नशे के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और जनजागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। कलेक्टर श्री मृणाल मीना ने बैठक में कहा कि अभियान अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में नशा मुक्ति विषय पर रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, संगोष्ठियां, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिताएं, मानव श्रृंखला तथा अन्य जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करे, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अभियान से जुड़ें और वर्ष 2029 तक नशामुक्त समाज के लक्ष्य को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं। बैठक के अंत में विभागवार जिम्मेदारियां तय की गईं तथा सभी अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।